



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2019/भाद्र 1, 1941

No. 261]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2019/BHADRA 1, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2019

(मामला सं. ओआई - 11/2019)

**विषय : मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास के आयात पर पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।**

**फा. सं. 6/15/2019-डी जी टी आर:** मै. सेंट गोबाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मै. सिंसेकॉम फ्लैट ग्लास इंडिया लिमिटेड, मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मै. असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड मुंबई (जिन्हें यहां इसके बाद "याचिकाकर्ता/आवेदक" भी कहा गया है), ने मलेशिया (जिसे यहां संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "क्लियर फ्लोट ग्लास" (जिसे यहां संबद्ध वस्तु अथवा विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां अधिनियम भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली भी कहा गया है) के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है ।

## विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) (जिसे यहां 'संबद्ध वस्तु' भी कहा गया है) "बी आई एस 14900:2000 के अनुसार नाममात्र मोटाई 4 मि.मि. से 12 मि.मि. (दोनों सम्मिलित) की रेंज वाली नाममात्र मोटाई का क्लियर फ्लोट ग्लास " हैं ।

3. फ्लोट ग्लास में सामान्य ग्लास का निर्माण करने वाली कच्ची सामग्री, जिसमें आम तौर पर सैंड, सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट), डोलोमाइट, लाइमस्टोन, साल्ट केक (सोडियम सल्फेट) आदि का उपयोग किया जाता है। अन्य सामग्रियों को कोलोरेट, शोधक एजेंटों के रूप में अथवा ग्लास की भौतिक और रासायनिक गुणों को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है। कच्ची सामग्रियों को एक बैच मिश्रण प्रक्रिया में मिश्रित किया जाता है तब इसे एक फर्नेस में, नियंत्रित अनुपात में, उपयुक्त कूलेंट (अपशिष्ट ग्लास) के साथ भरा जाता है जहां इसे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पर फर्नेस में गर्म किया जाता है। सामान्य फ्लैट ग्लास फर्नेस 9 मी. चौड़ी, 45 मी. लंबी होती है और 1200 टन ग्लास से ज्यादा अंतर्निहित मात्रा को करती है। एक बार पिघलने पर, ग्लास के तापमान को सजातीय विशिष्ट गुरुत्व को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर किया जाता है।
4. पी यू सी का प्रमुख रूप से निर्माण कार्यों, रेफ्रीजरेशन, दर्पण और आटोमोबाइल्स इंडस्ट्री आदि में प्रयोग किया जाता है। उत्पाद एक उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला ग्लास है। इसकी अंतर्निहित शक्ति, उच्च प्रकाशीय स्पष्टता, विकृति मुक्त चिकनी सतह आदि के कारण विभिन्न प्रयोगों के लिए उत्पादन के अनुप्रयोगों में वृद्धि हुई है।
5. पीयूसी को अध्याय शीर्ष 70 “ग्लास एवं ग्लासवेयर” के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और वर्गीकरण 8 अंकीय स्तर पर 70051090 है हालांकि इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप शीर्षों जैसे 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 और 7020 के अंतर्गत वर्गीकृत और आयातित किया जा रहा है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

#### समान वस्तु

6. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विशिष्टताओं, कीमत निर्धारण, वितरण व विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्रयोक्ता दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर भारत में याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

#### घरेलू उद्योग और आधार

7. याचिका मै. सेंट गोबाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मै. सिंसेकॉम फ्लैट ग्लास इंडिया लिमिटेड, मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मै. असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है।
8. उपलब्ध सूचना के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से किसी प्रकार से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में प्रमुख समानुपात (85 प्रतिशत) के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख)के अर्थों के भीतर याचिकाकर्ताओं को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन ऊपर उल्लिखित नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में पूरा उतरने के मापदंड को पूरा करता है।

#### शामिल देश

9. वर्तमान जांच में शामिल देश मलेशिया है (जिसे संबद्ध देश भी कहा गया है)।

#### सामान्य मूल्य

10. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वे मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए, सामान्य मूल्य के उचित निर्धारण के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत में भली-भांति समायोजित और यथा-उपगत अन्य कच्ची सामग्री की लागत, परिवर्तन लागत और अन्य व्ययों के आधार पर

तथा मलेशिया में प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात् सोडा एश की लागत आई टी सी ट्रेड मैप के आधार पर निर्धारित किया गया है।

### निर्यात कीमत

11. याचिकाकर्ताओं ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। कीमत समायोजन का दावा समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन सार-संभाल एवं निकासी प्रभार, कमीशन, ऋण लागत के कारण किया गया है।

### पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य, और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्टया संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन को दर्शाते हैं। इस संबंध में प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात कीमत की तुलना में अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत बाजार में संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं।

### क्षति और कारणात्मक संबंध

13. घरेलू उद्योग की क्षति का आकलन करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने कुल रूप में और भारत में उत्पादन और खपत, कीमत में हास, कीमत से कम कीमत पर बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणाम के रूप में स्थान ले रही क्षति के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा उत्पन्न घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही “क्षति” के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य विद्यमान हैं।

### पाटनरोधी जांच की शुरुआत

14. और जबकि प्राधिकारी ने प्रथमदृष्टया यह पाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति, एवं एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं। प्राधिकारी, एतद्वारा कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने, जो यदि लागू होता तो घरेलू उद्योग की ‘क्षति’ को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, नियमावली के नियम 5 की शर्तों में कथित पाटन और घरेलू उद्योग की परिणामी क्षति के निर्धारण के लिए एक जांच की शुरुआत करते हैं।

### जांच की अवधि (पी ओ आई)

15. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017, अप्रैल-2017 - मार्च, 2018 के आंकड़े तथा जांच की अवधि (पी ओ आई) शामिल हैं।

### सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे दिए गए पते पर निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं बताए गए तरीके से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है :

#### निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

17. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

### समय-सीमा

18. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच शुरूआत शुरूआत संबंधी अधिसूचना की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों और सॉफ्ट प्रतियों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

### गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में " गोपनीयता " का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-
- गोपनीय के रूप में अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और
  - अगोपनीय के रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।
21. "गोपनीय "या" अगोपनीय " अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर " गोपनीय "या" अगोपनीय " अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियों प्रत्येक के चार (4) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
22. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना अंतर्निहित होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
26. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**असहयोग**

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

**सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी**

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL TRADE REMEDIES)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd August, 2019

**(Case No: OI-11/2019)**

**Subject: Initiation of Anti-dumping investigation on the import of Clear Float Glass originating in or exported from Malaysia.**

**F. No. 6 /15/2019-DGTR** M/s. Saint-Gobain India Pvt Ltd, M/s. Sisecam Flat Glass India Ltd., M/s Gold Plus Glass Industries Ltd and M/s. Asahi India Glass Ltd, (hereinafter referred to as “petitioners/Applicants”) have filed a joint application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Clear Float Glass” (hereinafter also referred to as subject goods or product under consideration), originating in or exported from Malaysia (hereinafter also referred to as the subject country).

**Product under consideration:**

2. The product under consideration (PUC) for the purpose of present investigation is “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)”, the nominal thickness being as per BIS14900:2000 (hereinafter also referred to as the “subject goods”).
3. Float glass uses common glass-making raw materials, typically consisting of sand, soda ash (sodium carbonate), dolomite, limestone, salt cake (sodium sulfate) etc. Other materials may be used as colorants, refining agents or to adjust the physical and chemical properties of the glass. The raw materials are mixed in a batch mixing process, then fed together with suitable cullet (waste glass), in a controlled ratio, into a furnace where it is heated to approximately 1500°C. Common flat glass furnaces are 9 m wide, 45 m long, and contain more than 1200 tons of glass. Once molten, the temperature of the glass is stabilized to approximately 1200°C to ensure a homogeneous specific gravity.
4. The PUC finds major uses in construction, refrigeration, mirror and automobile industries etc. The product is a superior quality of glass. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface etc., the applications of the product have been increasing for different purposes.
5. The PUC is classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware” and the classification at the 8-digit level is 70051090 even though the same are being classified and imported under various sub-headings like 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 and 7020 of the Customs Tariff Act, 1975. The Customs classification is indicative only and in no way binding upon the scope of investigation.

**Like Article**

6. The petitioners have claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject country. Subject goods produced by the petitioners and imported from the subject country are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the petitioners in India are being treated as 'Like Article' within the meaning of the Rule 2 (d) to that being imported from the subject country.

**Domestic Industry & Standing**

7. The petition has been filed by M/s. Saint-Gobain India Pvt. Ltd, M/s. Sisecam Flat Glass India Ltd. M/s. Gold Plus Glass Industries Ltd and M/s. Asahi India Glass Ltd jointly.
8. As per the available information, the petitioners have neither imported the subject goods nor are related to any other producer/exporter of the subject goods in the subject country or any importer in India. Further, the petitioners account for a major proportion (85%) in Indian production of the subject goods. Therefore, the Authority has considered the petitioners as Domestic Industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

**Country Involved**

9. The country involved in the present investigation is Malaysia (also referred to as subject country)

**Normal value**

10. The Petitioners have claimed that they were not able to obtain reliable information in relation to prices of subject goods in Malaysia. Therefore, the normal value has been constructed based on major raw material price i.e. Soda ash in Malaysia based on ITC trade map data, and other raw material cost, conversion cost and other expenses as per best available information.

**Export Price**

11. The Petitioners have claimed export price on the basis of data published by DGCIS. Price adjustments have been claimed of account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and clearance charges, commission, credit cost.

**Dumping Margin**

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

**Injury and Causal Link**

13. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The petitioner has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling, capacity utilization, profitability, cash profits and return on capital employed. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

**Initiation of Anti-Dumping investigation**

14. And whereas the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby

initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

### **Period of Investigation**

15. The period of investigation (POI) for the present investigation is from April 2018 to March 2019 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the periods April 2015-March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.

### **Submission of information**

16. The known exporters in the subject country and its Government through its Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.

The Designated Authority  
Directorate General of Trade Remedies,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce

Government of India 4th Floor, Jeevan Tara Building, 5,  
Parliament Street, New Delhi-110001

17. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

### **Time limit**

18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

### **Submission of information on confidential basis**

20. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
  - i. One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - ii. The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.)
21. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in four (4) sets of each.
22. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are

- claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

27. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority